



Neutral Citation No.-2026:AHC:61306

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9988 वर्ष 2026

पवन

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : राम शिरोमणि यादव

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राम शिरोमणि यादव, की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अतुल कुमार कुशवाहा, और राज्य के विद्वान एजीए श्री बी.पी. सिंह, को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत, आवेदक सूरज की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें उसे मामला अपराध संख्या 489/2025 धारा 318(4), 308(2), 61(2)ए बीएनएस और 66डी आईटी अधिनियम, थाना बहजोई, जिला संभल में पंजीकृत किया गया है, में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और परोक्ष अभिप्राय के कारण इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और मौद्रिक लेनदेन के संबंध में बैंक प्राधिकारी को प्राप्त कुछ शिकायतों के आधार पर जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक 07.01.2026 से जेल में बंद है और वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी संख्या में मुकदमों की लंबितता के मद्देनजर, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।
4. इसके विपरीत विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।
5. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और बैंक प्राधिकारी को मौद्रिक लेनदेन के संबंध में प्राप्त कुछ शिकायतों के माध्यम से जांच के दौरान उसका नाम सामने आया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो 07.01.2026 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. सभी तथ्यों, उनकी प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने के बाद और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का मामला बनता है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।
7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-पवन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत अनुबंध और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (1) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (2) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
 - (3) आवेदक, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
 - (4) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
 - (5) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐमन

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।